

अध्याय 3

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट

1. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर में बदलने के लिए समर्पित है जो समावेशिता, इक्विटी और रहने लायक स्थितियों को बढ़ावा देकर अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक कल्याण, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के बजट का आकार 2014-15 के 36,766 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपये हो गया है। योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के आवंटन में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 के 17,700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 43,700 करोड़ रुपये हो गया।
2. दिल्ली में, आउटकम बजट का उपयोग कार्यनिष्पादन के उपकरण के रूप में किया जाता है जो बेहतर सेवा वितरण, निर्णय लेने में सुधार, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन का समय-समय पर मूल्यांकन करने और बेहतर योजना प्रबंधन के माध्यम से बजट लागत को प्रभावी बनाने में मदद करता है। इसका कार्यान्वयन बेहतर योजना प्रबंधन के माध्यम से बजटीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के द्वारा समग्र बजटीय ढांचे में लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।
3. दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आउटकम बजट में 22 विभाग शामिल हैं। प्रत्येक विभाग के भीतर, प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं की पहचान की गई और प्रत्येक योजना के लिए बारीकी से प्रमुख आउटपुट और परिणाम संकेतक स्थापित किए गए। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि ये संकेतक स्मार्ट (विशिष्ट, मापने योग्य, श्रेय देने योग्य, यथार्थवादी और लक्षित) मानदंड पर आधारित हों और विभागों के भीतर और सभी विभागों में समान कार्यक्रमों और योजनाओं से तुलनीय हों।
4. दिल्ली सरकार आउटकम बजट की एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है जो 'ऑन ट्रैक' और 'ऑफ ट्रैक' श्रेणियों के तहत आउटकम बजट के महत्वपूर्ण संकेतकों की स्थिति को स्पष्ट करती है।
5. जहां तक योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत निधियों के आवंटन और व्यय की स्थिति का संबंध है, यह अध्याय विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण, जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, सामाजिक क्षेत्रों, एजेंसीवार आदि के आंकड़े प्रदान करता है। 2016-17 तक बजट/व्यय को योजना-गैर योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इस अध्याय के तहत केवल योजना भाग पर चर्चा की गई है, क्योंकि 2017-18 से योजनाओं और स्थापना व्यय के तहत वर्गीकरण किया गया है। इस अध्याय में 2017-18 तथा उसके बाद के आंकड़ों में केवल योजना व्यय पर चर्चा की गई है।

पंचवर्षीय योजनाएं

6. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदित योजना परिव्यय और व्यय का विवरण 3.1 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.1

दिल्ली का पंचवर्षीय योजना का योजना परिव्यय और व्यय : 1951-2017

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाएं	योजना परिव्यय	कुल व्यय	योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय
1.	पहली पंचवर्षीय योजना 1951-1956	6.30	4.70	74.60
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-1961	17.00	15.37	90.41
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966	99.33	93.10	93.73
4.	चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-1974	168.77	155.16	91.94
5.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979	363.75	341.34	93.84
6.	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-1985	1039.38	1041.95	100.25
7.	सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990	2537.34	2631.47	103.71
8.	आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-1997	4500.00	6208.32	137.96
9.	नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002	15541.28	13465.09	86.64
10.	दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007	23000.00	22646.00	98.46
11.	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-2012	54799.15	53478.86	97.95
12.	बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017	90000.00	70497.04	78.33

*नोट : 2014-15 से योजना परिव्यय में सी.एस.एस. भी शामिल है।

7. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत व्यय केवल 4.70 करोड़ रुपये था जो 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई गुना बढ़कर 70497.04 करोड़ रुपये हो गया।
8. 2017-18 में, नीति आयोग, भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के बाद पंचवर्षीय योजनाओं की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया। 2017-18 से, राजस्व और पूंजीगत शीर्ष के तहत वर्गीकृत स्थापना और योजनाओं के तहत बजट तैयार किए जाते हैं।
9. 2017-18 से योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत बजट आवंटन और व्यय विवरण 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.2
दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

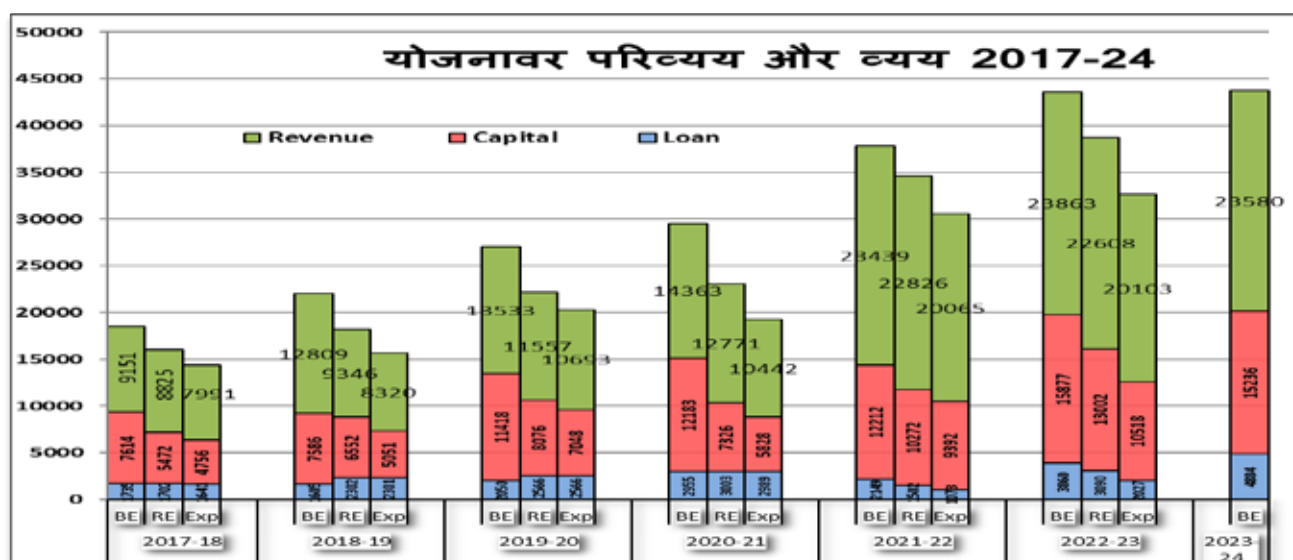
क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (ब.अ.)	परिव्यय (सं.अ.)	कुल व्यय	परिव्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय (सं.अ.)
1.	2017-18	18500	16000	14387	89.9
2.	2018-19	22000	18200	15672	86.1
3.	2019-20	27000	22200	20307	91.5
4.	2020-21	29500	23100	19259	83.4
5.	2021-22	37800*	34600	30531	88.2
6.	2022-23	43600	38700	32648	84.4
7.	2023-24	43700	-	-	-

*2021-22 में योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, क्योंकि कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों को "स्थापना बजट" (एफडी) से योजनाओं के बजट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, नागरिक आपूर्ति, जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र संबंधी सब्सिडी और जीआईए शामिल हैं।

10. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के तहत व्यय वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान में 91.5 प्रतिशत था जबकि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में घटकर 83.4 प्रतिशत रह गया और उसके बाद 2021-22 में यह थोड़ा और बढ़ा।
11. वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्व, पूंजीगत एवं ऋण के अंतर्गत बजट एवं व्यय का वर्षवार आवंटन विवरण 3.3 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.3
दिल्ली का योजना/कार्यक्रम/परियोजना परिव्यय और व्यय
(राजस्व, पूंजी और ऋण के अंतर्गत)

(करोड़ रुपये में)



नोट : योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजी आबंटन अनुदान की विस्तृत मांग (डीडीजी) से मेल नहीं खा सकता क्योंकि योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं में जीआईए पूंजी पूंजीगत भाग के अंतर्गत शामिल की जाती है जबकि डीडीजी में जीआईए पूंजी राजस्व भाग के अंतर्गत शामिल की जाती है।

12. राजस्व अनुभाग के तहत 2021-22 के दौरान बजट आवंटन 2017-18 में 50 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 62 प्रतिशत हो गया है, जिसका मुख्य कारण सब्सिडी और जीआईए को 'स्थापना बजट' से 'योजना बजट' में स्थानांतरित करना है।
13. योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए एजेंसी-वार व्यय विवरण 3.4 में प्रस्तुत किया गया है:

विवरण 3.4

योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के लिए जारी एजेंसी-वार व्यय/राशि

(करोड़ रुपये में)

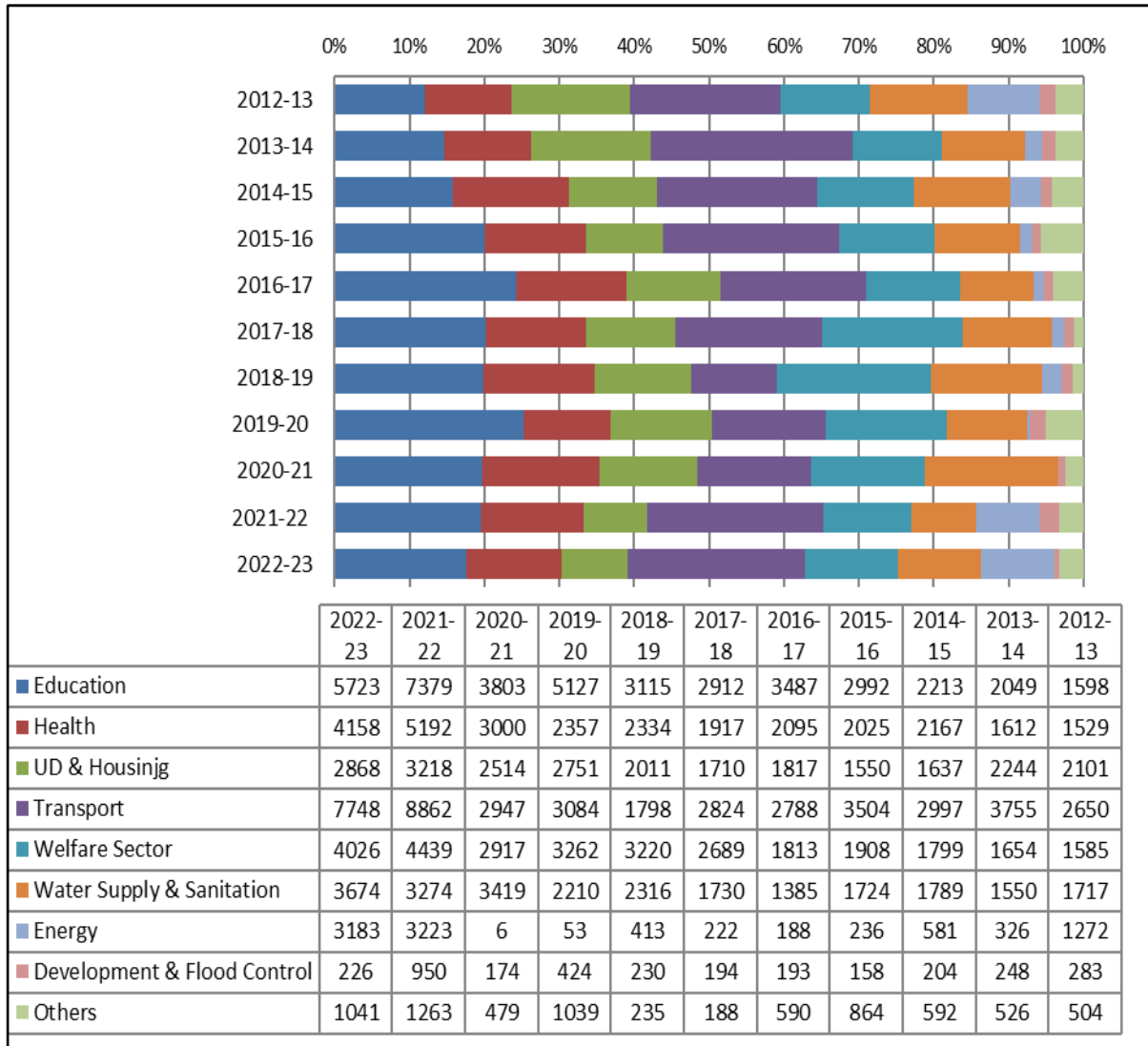
क्र. सं.	विभाग/एजेंसी	2017-18 (व्यय)	2018-19 (व्यय)	2019-20 (व्यय)	2020-21 (व्यय)	2021-22 (व्यय)	2022-23 (व्यय)	2022-23 (ब.अ.)
1.	जीएनसीटीडी के विभाग	10818.41	12310.99	15648.55	12989.32	26536.62	26116.07	35413.47
2.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	780.98	219.32	1009.48	1024.80	790.96	203.14	-
3.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	535.98	117.12	595.92	555.00	507.56	104.24	-
4.	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	423.31	299.17	661.57	537.60	470.90	170	-
5.	एमसीडी	-	-	-	-	-	2168.83	2659.36
6.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	2.41	2.65	2.50	99.37	1.64	54.51	-
7.	दिल्ली जल बोर्ड	1730.00	2315.98	2210.00	3419.00	2164.27	3674.33	5442.00
8.	डीयूएसआइबी	96.25	406.70	178.89	633.26	58.54	155.69	185.17
9.	दिल्ली छावनी परिषद	0.15	0.10	0.11	0.30	0.28	0.78	-
	कुल	14387.47	15672.03	20307.02	19258.65	30530.77	3264.76	43700.00

14. योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का क्षेत्रवार व्यय चार्ट 3.1 में प्रस्तुत किया गया है:

चार्ट 3.1

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का क्षेत्रवार व्यय

(करोड़ रुपये में)



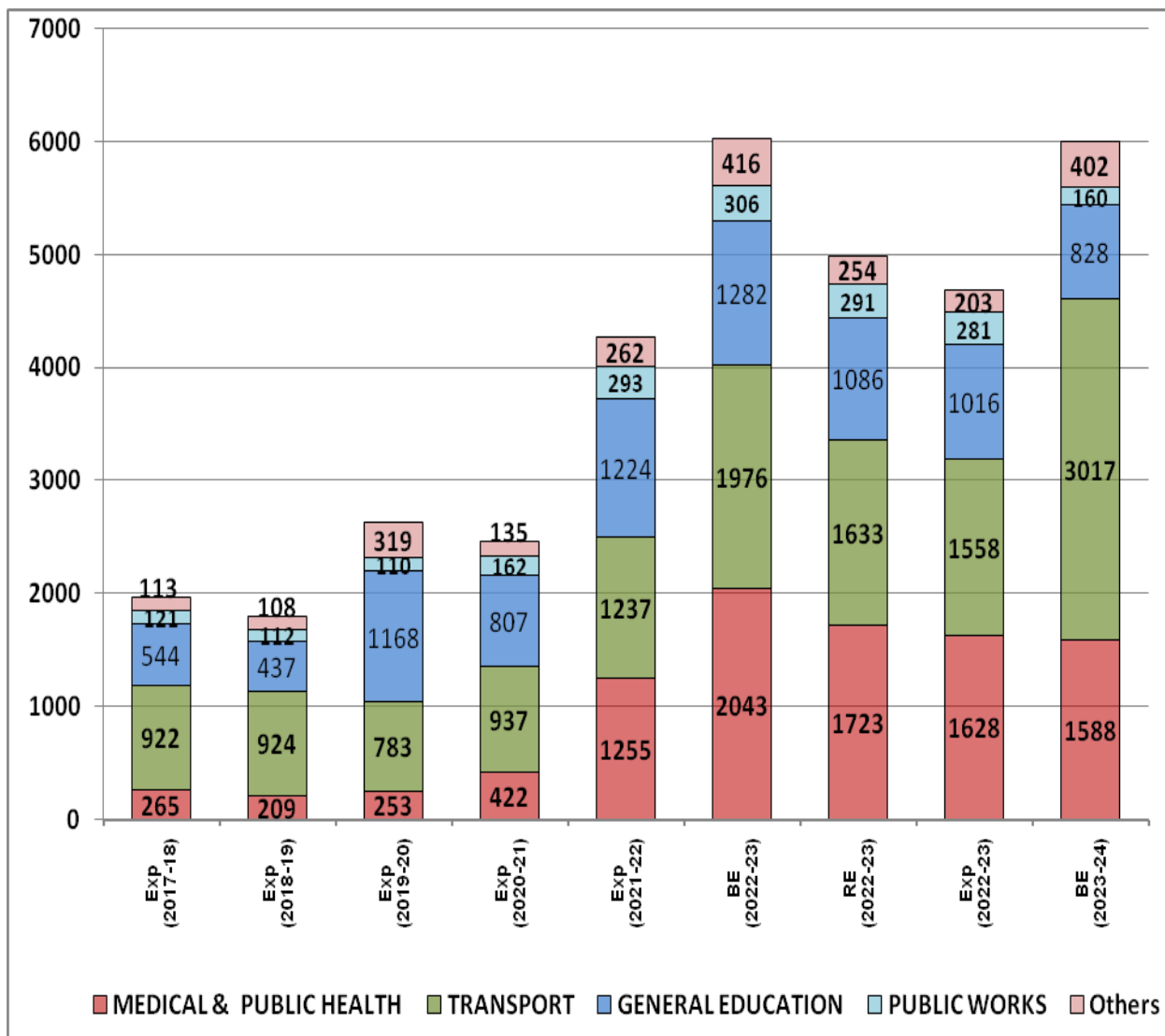
नोट: शिक्षा में सामान्य शिक्षा क्षेत्र (जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है) तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवा क्षेत्र और मिड डे मील, डीटीटीई (श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्र, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली अभिलेखागार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं)।

15. उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2022-23 के दौरान प्रमुख व्यय शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन तथा कल्याण क्षेत्रों पर किया गया है।
16. लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय एवं वर्ष 2023-24 का बजट आवंटन विवरण 3.5 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.5

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का पूंजीगत व्यय एवं बजट आवंटन—(लोक निर्माण विभाग)

(करोड़ रुपये)

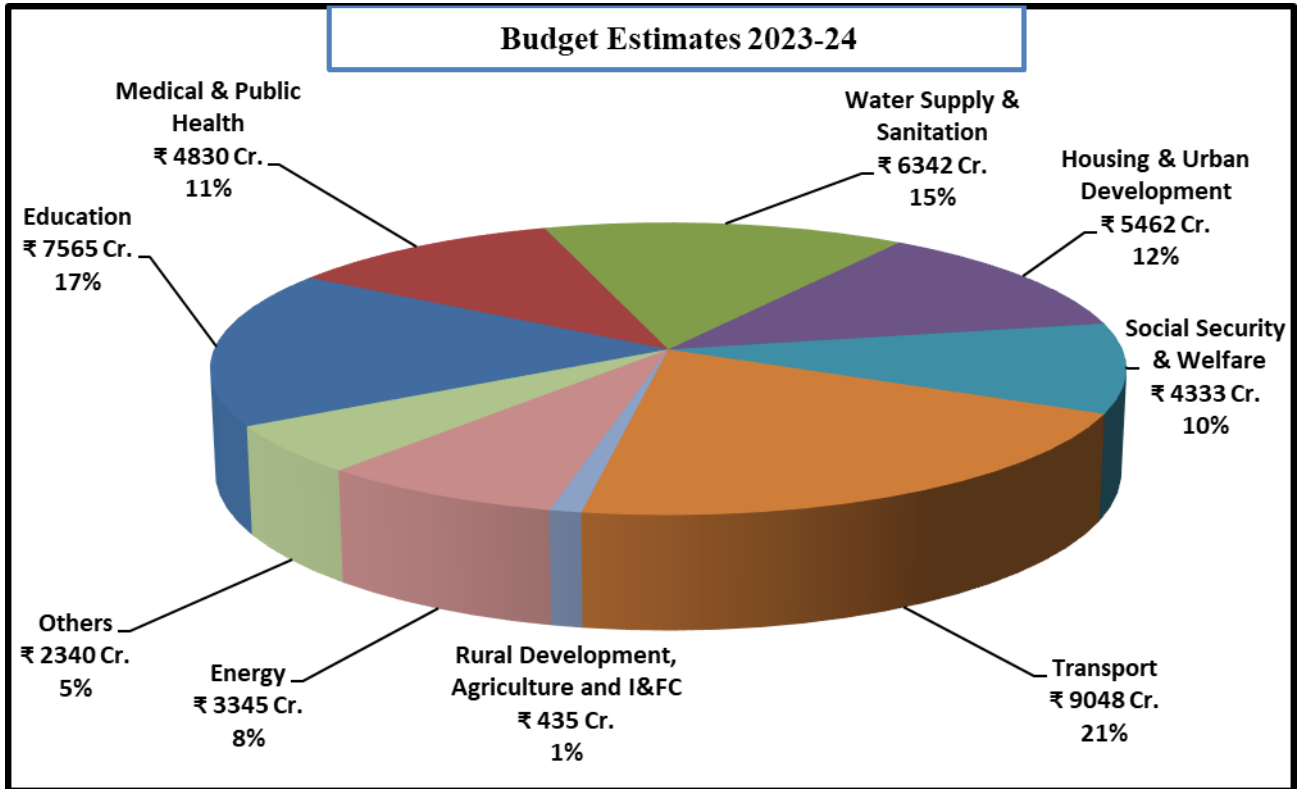


* इसमें कृषि और संबद्ध सेवाएं, महिला एवं बाल विकास और अजा/अजजा/अपिव क्षेत्र का कल्याण सहित अन्य शामिल है।

- योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं—2023—24 के प्राथमिकता वाले क्षेत्र का बजट आवंटन चार्ट 3.2 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 3.2

योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के प्राथमिकता क्षेत्र का बजट आवंटन-2023-24



* इसमें सामान्य शिक्षा क्षेत्र (जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है) तकनीकी शिक्षा क्षेत्र, कला और संस्कृति क्षेत्र, खेल और युवा सेवाएं क्षेत्र और मिड डे मील, डीटीटीई (श्रम और श्रम कल्याण क्षेत्र, एनसीसी (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली अभिलेखागार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

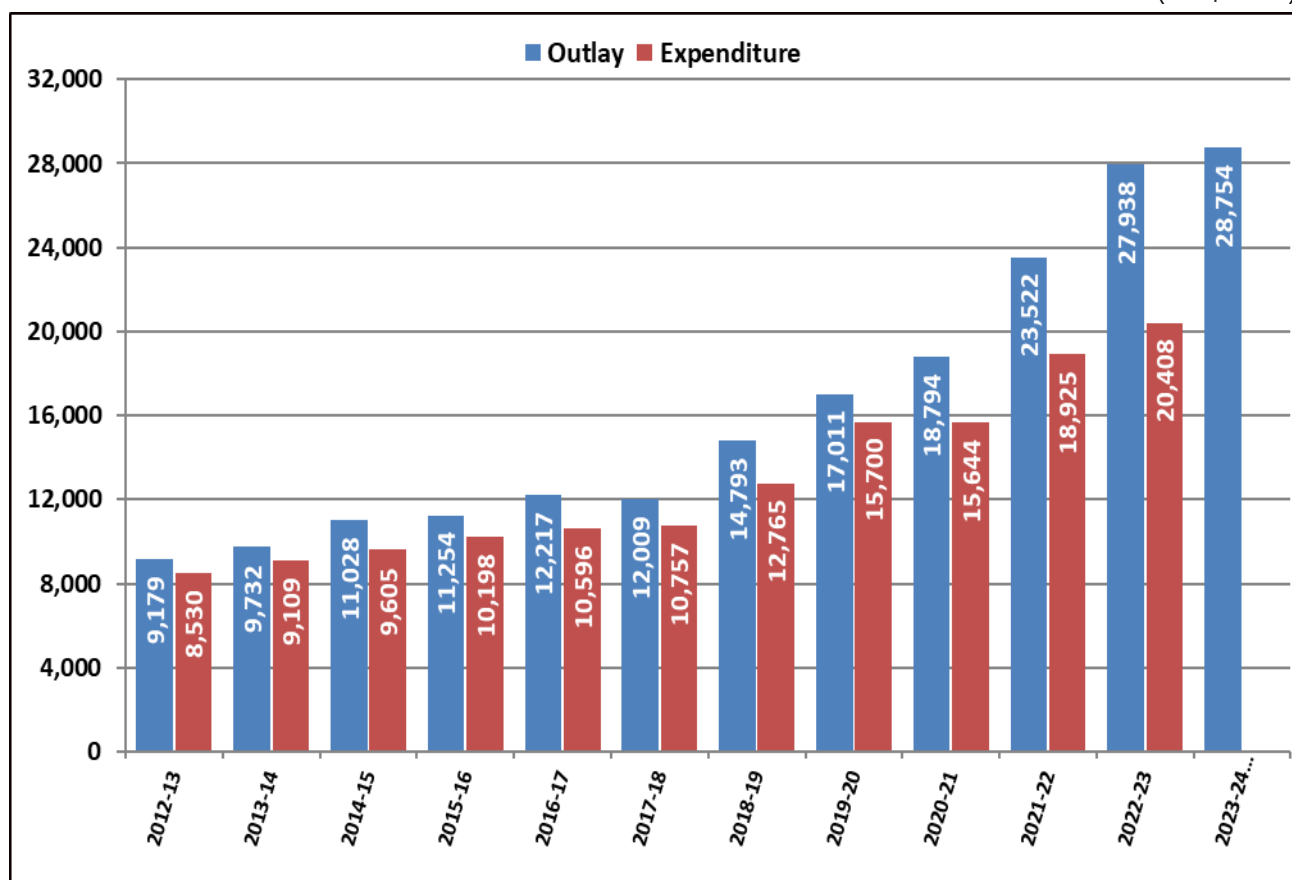
इसमें म. एवं बा वि, अजा/अजजा/अपिव कल्याण, सामाजिक कल्याण, नागरिक आपूर्ति, पोषण (एमडीएम को छोड़कर), श्रम और श्रमिक कल्याण (डीटीटीई को छोड़कर), वजन और माप (पीडब्ल्यूडी), श्रम और रोजगार (पीडब्ल्यूडी) शामिल हैं।

18. चार्ट 3.2 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिवहन क्षेत्र को सबसे अधिक हिस्सा यानी 9048 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत), आवंटित किया गया है, इसके बाद शिक्षा क्षेत्र को 7565 करोड़ रुपये (17 प्रतिशत) फिर जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को 6342 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत) का बजट आवंटन किया गया है फिर आवास, शहरी विकास को 5462 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) का, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को 4830 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत) का फिर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र को 4333 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) का बजट आवंटन किया गया है और फिर ऊर्जा को 8 प्रतिशत बजट आवंटन किया गया है।
19. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान और 2017-18 और उसके बाद से सामाजिक सेवा क्षेत्र के योजना/कार्यक्रमों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का परिचय एवं व्यय, चार्ट 3.3 में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम और रोजगार, नागरिक आपूर्ति और पोषण क्षेत्र शामिल हैं।

चार्ट 3.3

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान और 2017-18 से सामाजिक सेवा क्षेत्र के योजना/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये)



20. 10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में सामाजिक सेवा क्षेत्र का आवंटन, विवरण 3.6 में प्रस्तुत किया गया है।

विवरण 3.6

10वीं, 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में सामाजिक सेवा क्षेत्र का आवंटन

(करोड़ रुपये)

क्र. स.	पंच वर्षीय योजना 10वीं	कुल योजना परिव्यय (सं.अ.)	सा.से.क्षेत्र के तहत योजना परिव्यय (सं.अ.)	कुल परिव्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	कुल व्यय	सा.से.क्षेत्र के तहत व्यय	कुल व्यय में सा.से. क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
1	10वीं (2002-2007)	24342.67	12353.24	50.74	22846.98	11050.42	48.36
2	11वीं (2007-2012)	55900.00	32338.40	57.85	53478.86	30547.74	57.12
3	12वीं (2012-2017)	78950.00	53410.89	67.65	70497.04	48038.52	68.14

21. सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन :

विवरण 3.7

सामाजिक सेवा क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	वर्ष	कुल योजना परिव्यय (सं.अ.)	सा.से.क्षेत्र के तहत योजना परिव्यय (सं.अ.)	कुल परिव्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	कुल व्यय	व्यय	कुल व्यय में सा.से.क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी
1.	2017-18	16000	12009	75.1	14387	10757	74.8
2.	2018-19	18200	14793	81.3	15672	12765	81.5
3.	2019-20	22200	17011	76.6	20307	15700	77.3
4.	2020-21	23100	18794	81.4	19259	15644	81.2
5.	2021-22	34600	21730	63.5	30531	18925	61.9
6.	2022-23	38700	23936	61.9	32648	20408	62.5
7.	2023-24	43700 (ब.अ.)	28754 (ब.अ.)	65.8			

सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में 2017-18 से 2022-23 के दौरान सं.अ. के संदर्भ में बढ़ोतरी (यानी 12009 करोड़ से 23936 करोड़ की वृद्धि) की प्रवृत्ति रही है। हालांकि, प्रतिशत के लिहाज से इसमें 2021-22 और 2022-23 में गिरावट आई है। इसका कारण योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए बजट के कुल आकार में वृद्धि है। यह वृद्धि इस लिए हुई क्योंकि 2021-22 में मुख्य रूप से गैर-सामाजिक क्षेत्र के कुछ मदों (यानी परिवहन और ऊर्जा आदि) के संबंध में जीआईए और सब्सिडी को स्थापना बजट (एफडी) से योजना बजट में स्थानांतरित करने के कारण योजना बजट संशोधित किया गया था।

22. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के योजना परिव्यय और व्यय से संबंधित अन्य सांख्यिकीय जानकारी तालिका 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7 में देखी जा सकती है।
23. दिल्ली सरकार ने हाल के वर्षों में दिल्ली के विकास में भारी निवेश किया है और सराहनीय आर्थिक प्रगति की है और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के कल्याण पर विशेष ध्यान देते हुए सामान्य नागरिकों का कल्याण किया है।

अध्याय एक नज़र में

➤	दिल्ली के बजट का आकार 2014-15 के 36766 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 78800 करोड़ रुपये हो गया है।
➤	योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत बजट के आवंटन में भी उत्कृष्ट वृद्धि देखी गई है, जो 2014-15 में 17700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 (ब.अ.) में 43700 करोड़ रुपये हो गई है।
➤	2023-24 के दौरान, सबसे अधिक बजट आवंटन परिवहन क्षेत्र को किया गया है यानी 9048 करोड़ रुपये (21%), इसके बाद शिक्षा क्षेत्र को 7565 करोड़ रुपये (17%) और जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र को 6342 करोड़ रुपये (15%) का बजट आवंटन किया गया है।